[2020] 3 एस सी आर

उर्मिला देवी और अन्य

बनाम

शाखा प्रबंधक, राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड और एक अन्य

(2020 की दीवानी अपील सं.838)

30 जनवरी, 2020

[भारत के मुख्य न्यायाधीश एस. ए. बोबडे और माननीय न्यायमूर्ति श्री बी. आर. गवई और सूर्यकांत]

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 – धारा 173 – अपील – प्रति आपत्तियाँ - पोषणीयता- दावेदार-अपीलकर्ता संख्या 1 के पति (जो अपीलकर्ता संख्या 2-4 के पिता और अपीलकर्ता संख्या 5 के पुत्र भी थे) की दुर्घटना की सुनवाई योग्यता – मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने बीमा कंपनी को दावेदारों को 2,47,500/- रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया – बीमा कंपनी द्वारा उच्च न्यायालय में दायर अपील को चूक के कारण खारिज कर दिया गया – अपीलकर्ताओं द्वारा दायर प्रति आपत्ति को सुनवाई योग्य न मानते हुए खारिज कर दिया गया – निर्णय: 1992 के मोटर वाहन नियमों की धारा 249 के मद्देनजर, उच्च न्यायालय ने सही माना कि दावेदार प्रति-आपत्ति दायर करने के हकदार थे – हालाँकि, इसने आपत्ति दायर करने के उक्त अधिकार को केवल तभी प्रतिबंधित किया जब बीमा कंपनी द्वारा मुआवजे की राशि को चुनौती देते हुए अपील दायर की गई हो न कि केवल वर्तमान मामले की तरह मुआवजा देने के अपने दायित्व को - धारा 173 में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति किसी पंचाट से व्यथित है दावा न्यायाधिकरण, उपधारा (2) के अधीन, उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।

नियम 249(3) दर्शाता है कि उप-नियम (1) और (2) में दिए गए प्रावधान के अलावा, दं.प्र.सं. दंड प्रक्रिया (संहिता) के नियम XLI और नियम XXI के प्रावधान धारा 173 के तहत उच्च न्यायालय में की गई अपीलों पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे - धारा 173 का संयुक्त पाठ; नियम 249 और नियम XLI, नियम 22 से पता चलता है कि किसी भी पक्ष के अपील के अधिकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है - कोई भी पक्ष जो पंचाट के किसी भी भाग से व्यथित है, अपील करने का हकदार होगा - इस प्रकार, कोई भी उतरदाता, भले ही उसने डिक्री के किसी भी भाग के खिलाफ अपील न की हो, अपने पक्ष में निष्कर्ष का समर्थन करने के अलावा, डिक्री पर कोई भी प्रति-आपति लेने का भी हकदार है, जो वह अपील के माध्यम से ले सकता था - इसके अलावा, नियम 22(4) नियम XLI में विशेष रूप से प्रावधान है कि यदि मूल अपील वापस ले ली जाती है या चूक के कारण खारिज कर दी जाती है, तब भी प्रति-आपत्ति पर सुनवाई की जाएगी और उसका निर्धारण किया जाएगा - इसलिए, भले ही बीमा कंपनी की अपील चूक के कारण खारिज कर दी गई हो और वह अपील को पुनर्जीवित करने में रुचि नहीं रखती हो, फिर भी उच्च न्यायालय को अपीलकर्ताओं की आपतियों का गुण-दोष के आधार पर निर्णय - आक्षेपित निर्णय अपास्त - मामला उच्च न्यायालय को प्रति-आपत्ति के गुण-दोष के आधार पर निर्णय हेतु प्रेषित - दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 – या. XLI, नियम 22; या.XXI - बिहार मोटर वाहन नियम, 1992 - नियम 249 - मध्यस्थता अधिनियम, 1940 - धारा 39

अ**पील स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:**

1.1 बिहार मोटर वाहन नियम, 1992 के नियम 249 के मद्देनजर, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर सही रूप से पहुँचा है कि दावेदार प्रति-आपत्ति दायर करने के हकदार होंगे। हालाँकि, इसने दावेदारों के प्रति-आपत्ति दायर करने के अधिकार को केवल

तभी प्रतिबंधित कर दिया जब बीमा कंपनी द्वारा मुआवजे की राशि को चुनौती देते हुए अपील दायर की गई हो। यह अभिनिर्धारित किया गया कि जब बीमा कंपनी ने मुआवजे की राशि को चुनौती नहीं दी है, बल्कि केवल इस आधार पर मुआवजा देने के अपने दायित्व को चुनौती दी है कि चालक और/या वाहन के मालिक द्वारा नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया गया है, तो दावेदारों के कहने पर प्रति-आपत्ति मान्य नहीं होगी। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 173 में प्रावधान है कि दावा न्यायाधिकरण के किसी निर्णय से व्यथित कोई भी व्यक्ति, उसकी उप-धारा (2) के प्रावधानों के अधीन, उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। धारा 173 की उपधारा (2) के तहत लगाया गया प्रतिबंध दावा न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय के विरुद्ध अपील दायर न करने के संबंध में है, यदि अपील में आक्षेपित राशि दस हजार रुपये से कम है। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने स्वयं यह टिप्पणी की कि बिहार मोटर वाहन नियम, 1992 के नियम 249 के मद्देनजर, प्रति-आपत्ति की वैधता के संबंध में कोई मुद्दा नहीं हो सकता। बिहार मोटर वाहन नियम, 1992 के नियम 249 का उप-नियम (3) यह दर्शाता है कि उप-नियम (1) और (2) में दिए गए प्रावधानों के अलावा, दं.प्र.सं. की पहली अनुसूची में आदेश XLI और आदेश XXI के प्रावधान मोटर वाहन अधिनियम की धारा 173 के तहत उच्च न्यायालय में दायर अपीलों पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 173 के प्रावधानों; बिहार मोटर वाहन नियम, 1992 के नियम 249 और दं.प्र.सं. के आदेश XLI नियम 22 के संयुक्त पठन से यह पता चलता है कि किसी भी पक्ष के अपील के अधिकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यह स्पष्ट है कि पंचाट के किसी भी भाग से व्यथित कोई भी पक्ष अपील करने का हकदार होगा। यह भी स्पष्ट है कि कोई भी उतरदाता, भले ही उसने अपने पक्ष में दिए गए निष्कर्ष का समर्थन करने के अलावा, पंचाट के किसी भी भाग के विरुद्ध अपील न की हो, वह डिक्री पर कोई भी प्रति-आपति लेने का भी हकदार है जो वह अपील के माध्यम से ले सकता था। [कंडिका 15, 22-24][505-डी-ई; 511-ई-जी]

1.2 जब किसी अपील में अपीलकर्ता उन आधारों में से कोई भी उठा सकता था जिनसे वह व्यथित है, तो न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि किसी उतरदाता को दूसरे पक्ष द्वारा दायर अपील में प्रति-आपत्ति दायर करने से कैसे वंचित किया जा सकता है, जिसमें पंचाट के उस भाग को चुनौती दी गई हो जिससे वह व्यथित था। उच्च न्यायालय द्वारा किया गया उक्त भेद मोटर वाहन अधिनियम की धारा 173; बिहार मोटर वाहन नियम, 1992 के नियम 249; और दं.प्र.सं. के आदेश XLI नियम 22 के प्रावधानों के संयुक्त पठन के अनुरूप नहीं है। प्रतिवादियों (बीमा कंपनी) द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में प्रार्थना खंड से यह देखा जा सकता है कि संपूर्ण पंचाट को प्रतिवादियों-बीमा कंपनी द्वारा चुनौती दी गई थी। इतना ही नहीं, बल्कि अपीलकर्ताओं (दावेदारों) को भी उक्त अपील में पक्षकार उतरदाता के रूप में शामिल किया गया था। ऐसी परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने यहाँ अपीलकर्ताओं (दावेदारों) की आपत्ति पर गुण-दोष के आधार पर विचार करने से इनकार करके गलती की। दं.प्र.सं. के आदेश XLI के नियम 22 के उप-नियम (4) में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि भले ही मूल अपील वापस ले ली जाए या चूक के कारण खारिज कर दी जाए, फिर भी अन्य पक्षों को ऐसी सूचना देने के बाद, जैसा न्यायालय उचित समझे, आपत्ति पर सुनवाई और निर्णय किया जाएगा। इसलिए, भले ही बीमा कंपनी की अपील चूक के कारण खारिज कर दी गई हो और बीमा कंपनी ने प्रस्तुत किया हो कि वे अपील को पुनर्जीवित करने में रुचि नहीं रखते हैं, फिर भी उच्च न्यायालय को यहाँ अपीलकर्ताओं की आपत्ति पर गुण-दोष के आधार पर और कानून के अनुसार निर्णय करना आवश्यक था। [कंडिका 25-27][512-सी-जी]

1.3 आक्षेपित निर्णय और आदेश को अभिखंडित और अपास्त किया जाता है। वर्तमान अपीलकर्ताओं द्वारा दायर प्रति-आपत्ति पर उसके गुण-दोष के आधार पर निर्णय हेतु मामला उच्च न्यायालय को वापस भेजा जाता है। [अनुच्छेद 28] [512-एच; 513-ए]

दिल्ली नगर निगम एवं अन्य बनाम अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं खुफिया एजेंसी लिमिटेड **(2004) 3 एससीसी 250 : [2003] 1 एससीआर 951;** *बहादुरमल बनाम बिजातुन्निसा बेगम* **एआईआर 1964 आंध्र प्रदेश 365;** *इनायतुल्लाह खान बनाम दीवानचंद महाजन* **एआईआर 1959 मध्य प्रदेश 58;** *रामाश्रय सिंह एवं अन्य बनाम बिभीषण सिन्हा* **एआईआर 1950 कोलकता 372;** *बारू राम बनाम प्रसन्नी* **एआईआर 1959 एससी 93 : [1959] एससीआर 1403;** *अधीक्षण अभियंता एवं अन्य बनाम बी. सुब्बा रेड्डी* **(1999) 4 एससीसी 423 : [1999] 2 एससीआर 880 -संदर्भित।**

<u>नजीर संदर्भ</u>

[2003] 1 एससीआर 951	**कंडिका 16**	**में संदर्भित**
एआईआर 1964 आंध्र प्रदेश 365	**कंडिका 19**	**में संदर्भित**
एआईआर 1959 मध्य प्रदेश 58	**कंडिका 19**	**में संदर्भित**
एआईआर 1950 कल 372	**कंडिका 19**	**में संदर्भित**
[1959] एससीआर 1403	**कंडिका 20**	**में संदर्भित**
[1999] 2 एससीआर 880	**कंडिका 20**	**में संदर्भित**

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2020 की दीवानी अपील संख्या 838

पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 21.01.2016 से 2011 की विविध अपील संख्या 521 में निर्णय एवं आदेश से

शिवम सिंह, रोहित कुमार सिंह, हरप्रीत सिंह गुप्ता, गुरु शरण मौर्य, अनिमेष कुमार, सुमित कुमार, राणा प्रशांत, नीरज शेखर, अपीलकर्ताओं के लिए अधिवक्तागण।

अशोक कुमार शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता, परमानंद गौड़, क्षितिज मुद्गल, एकांश बंसल, अखिल शर्मा, उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्तागण।

<u>निर्णय</u>

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निर्णय सुनाया गया:

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

3. वर्तमान अपील, पटना उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा विविध अपील संख्या 521/2011 में पारित दिनांक 21.01.2016 के निर्णय और आदेश को चुनौती देती है, जिसमें दावेदार की प्रति-आपत्ति को अस्वीकार्य माना गया है।

4. वर्तमान अपील के निर्णय के लिए आवश्यक तथ्य, निम्नलिखित हैं:

5. 2.5.2008 को, अपीलकर्ता संख्या 1 के पति, अपीलकर्ता संख्या 2 से 4 के पिता और अपीलकर्ता संख्या 5 के पुत्र, संजय तांती का एक दुर्घटना में निधन हो गया जब वह टाटा मैक्सी से लदमा से गोराडीह जा रहे थे। अपीलकर्ताओं ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (जिसे आगे "मोटर वाहन अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 166 के तहत एक दावा याचिका दायर की। वाहन के मालिक को विपक्षी संख्या 1 के रूप में शामिल किया गया; वाहन के चालक को उतरदाता संख्या 2 के रूप में शामिल किया गया, जबकि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे "बीमा कंपनी" कहा जाएगा) को उतरदाता संख्या 3 और 4 के रूप में शामिल किया गया।

6. बीमा कंपनी का दावा था कि वाहन के चालक और मालिक ने बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया है और इसलिए वे मुआवजे के भुगतान के लिए

उत्तरदायी नहीं हैं।

7. मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (जिसे आगे "न्यायाधिकरण" कहा जाएगा) ने दिनांक 29.1.2011 के निर्णय और आदेश के तहत, बीमा कंपनी के इस तर्क को खारिज कर दिया कि चालक और वाहन के मालिक ने नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया था और दावा याचिका को स्वीकार करते हुए, बीमा कंपनी को दिनांक 29.1.2011 आदेश के अनुसार दावेदारों को 2,47,500/- रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।

8. विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय और पंचाट से व्यथित होकर, बीमा कंपनी ने पटना उच्च न्यायालय के समक्ष विविध अपील संख्या 521 वर्ष 2011 प्रस्तुत की, जिसमें तर्क दिया गया कि विद्वान न्यायाधिकरण ने गलती से उस पर दायित्व आरोपित कर दिया था। उक्त अपील में, अपीलकर्ताओं द्वारा एक प्रति-आपत्ति दायर की गई। जब अपील सुनवाई के लिए आई, तो यह देखा गया कि अपील को कार्यालय आपत्तियों के अभाव में खारिज कर दिया गया था और अपीलकर्ताओं (बीमा कंपनी) के अधिवक्ता ने कहा कि अपीलकर्ता (बीमा कंपनी) अपील को पुनर्जीवित करने में रुचि नहीं रखते थे। इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा अपील का निपटारा कर दिया गया। जहाँ तक वर्तमान अपीलकर्ताओं (दावेदारों) की प्रति-आपत्ति का संबंध है, उच्च न्यायालय ने दिनांक 21.01.2016 के आक्षेपित निर्णय और आदेश के माध्यम से यह माना कि जब बीमा कंपनी द्वारा दायर अपील केवल मुआवजे का भुगतान करने के अपने दायित्व से इनकार करने तक ही सीमित है, तो ऐसी स्थिति में दावेदारों की ओर से अपील के रूप में की गई प्रति-आपत्ति मान्य नहीं होगी। हालाँकि, यह माना गया कि यदि अपील में बीमा कंपनी मुआवजे की राशि को चुनौती देती है, तो ऐसी स्थिति में, दावेदार (दावेदारों) को दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 (जिसे आगे "दं.प्र.सं." कहा जाएगा) के आदेश XLI नियम 22 के अनुसार आपत्ति दर्ज करने का अधिकार होगा और इस प्रकार, प्रति-आपत्ति को अस्वीकार्य

मानते हुए खारिज कर दिया।

9. बिहार मोटर वाहन नियम, 1992 के नियम 249 के मद्देनजर पटना उच्च न्यायालय ने माना है कि यदि बीमा कंपनी ने दावेदार को दिए गए मुआवजे की राशि को चुनौती दी है, तो बीमा कंपनी द्वारा दायर अपील में दावेदार(ओं) के लिए प्रति-आपत्ति दायर करने में कोई बाधा नहीं है। हालाँकि, इसने यह माना कि यदि बीमा कंपनी द्वारा दायर अपील केवल वाहन मालिक और/या वाहन चालक द्वारा बीमा पॉलिसी की शर्तों और नियमों के उल्लंघन के आधार पर मुआवजे का भुगतान करने के अपने दायित्व तक ही सीमित है, तो दावेदार द्वारा दायर प्रति-आपत्ति मान्य नहीं होगी। यह माना गया है कि ऐसे मामले में दावेदार(ओं) को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 173 के तहत अपील दायर करने का अधिकार होगा।

10. व्यथित होने के कारण, अपीलकर्ता विशेष अनुमति द्वारा वर्तमान अपील के माध्यम से हमारे समक्ष उपस्थित हैं।

11. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करके पूरी तरह से गलती की है कि दावेदारों द्वारा दायर की गई आपत्ति स्वीकार्य नहीं थी क्योंकि अपीलकर्ता- बीमा कंपनी ने मुआवजे की राशि को चुनौती नहीं दी है।

12. इसके विपरीत, बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं की प्रति-आपत्ति को सही ढंग से खारिज कर दिया है। यह तर्क दिया जाता है कि चूँकि बीमा कंपनी ने अपील दायर नहीं की थी, इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा प्रति-आपत्ति को सही ढंग से खारिज कर दिया गया।

13. वर्तमान अपील के लिए प्रासंगिक, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 173

और दं.प्र.सं. के आदेश XLI नियम 22 के प्रावधान इस प्रकार हैं:

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 173

"173. अपीलें। - (1) उप-धारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, दावा अधिकरण के किसी निर्णय से व्यथित कोई भी व्यक्ति, निर्णय की तिथि से नब्बे दिनों के भीतर, उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है:

बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई कोई अपील, जिसे ऐसे निर्णय के अनुसार कोई राशि अदा करनी है, उच्च न्यायालय द्वारा तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि उसने उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित तरीके से पच्चीस हजार रुपये या इस प्रकार दी गई राशि का पचास प्रतिशत, जो भी कम हो, जमा नहीं कर दिया हो:

बशर्ते कि उच्च न्यायालय उक्त नब्बे दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद भी अपील पर विचार कर सकता है, यदि वह संतुष्ट हो कि अपीलकर्ता को पर्याप्त कारणों से समय पर अपील दायर करने से रोका गया था।

(2) दावा न्यायाधिकरण के किसी भी पंचाट के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जाएगी यदि अपील में आक्षेपित राशि दस हजार रुपये से कम है।

दं.प्र.सं. का आदेश XLI नियम 22

"22. सुनवाई के बाद उतरदाता डिक्री पर इस प्रकार आपत्ति कर सकता है मानो उसने अलग अपील की हो।—(1) कोई भी उतरदाता, भले ही उसने डिक्री के किसी भी भाग के विरुद्ध अपील न की हो, न केवल डिक्री का समर्थन कर सकता है, बल्कि यह भी कह सकता है कि किसी भी मुद्दे के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय में उसके विरुद्ध दिया गया निर्णय उसके पक्ष में होना चाहिए था; और डिक्री पर कोई भी प्रति-आपत्ति भी कर सकता है जो वह अपील के माध्यम से कर सकता था, बशर्ते उसने अपील की सुनवाई के लिए

नियत दिन की सूचना उसे या उसके अधिवक्ता को तामील किए जाने की तिथि से एक माह के भीतर, या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर, जिसे अपीलीय अदालत अनुमति देना उचित समझे, अपीलीय न्यायालय में ऐसी आपत्ति दर्ज कर दी हो।

स्पष्टीकरण —न्यायालय के किसी निष्कर्ष से व्यथित उतरदाता जिस निर्णय पर अपील की गई डिक्री आधारित है, इस नियम के तहत, डिक्री के संबंध में प्रति-आपत्ति दर्ज कर सकता है, जहाँ तक वह उस निष्कर्ष पर आधारित है, भले ही न्यायालय के निर्णय के कारण कोई अन्य निष्कर्ष जो वाद के निर्णय के लिए पर्याप्त है, डिक्री, पूर्णतः या आंशिक रूप से, उतरदाता के पक्ष में है।

(2) **आपत्ति का प्रारूप और उस पर लागू प्रावधान।** - ऐसी प्रति-आपत्ति एक ज्ञापन के रूप में होगी और नियम 1 के प्रावधान, जहाँ तक वे अपील ज्ञापन के प्रारूप और विषय-वस्तु से संबंधित हैं, उस पर लागू होंगे।

(3) * * *

(4) जहाँ, किसी मामले में, जिसमें किसी उतरदाता ने इस नियम के अंतर्गत आपत्ति ज्ञापन दायर किया है, मूल अपील वापस ले ली जाती है या चूक के कारण खारिज कर दी जाती है, वहाँ इस प्रकार दायर की गई आपत्ति पर अन्य पक्षों को ऐसी सूचना देने के बाद सुनवाई और निर्णय किया जा सकता है, जैसा न्यायालय उचित समझे।

(5) निर्धन व्यक्तियों द्वारा अपील से संबंधित प्रावधान, जहाँ तक उन्हें लागू किया जा सके, इस नियम के अंतर्गत किसी आपत्ति पर लागू होंगे।

14. बिहार मोटर वाहन नियम, 1992 का नियम 249 इस प्रकार है:

"249. अपील की विधि। - (1) दावा न्यायाधिकरण के विरुद्ध प्रत्येक अपील, अपीलकर्ता या उच्च न्यायालय के किसी अधिवक्ता या न्यायवादी द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन के रूप में

प्रस्तुत की जाएगी, जिसे आवेदक द्वारा विधिवत अधिकृत किया गया हो और उच्च न्यायालय या उसके द्वारा इस संबंध में नियुक्त किसी अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। ज्ञापन के साथ पंचाट की एक प्रति संलग्न होगी।

(2) ज्ञापन में संक्षेप में और जिला शीर्षकों के अंतर्गत उस निर्णय पर आपत्ति के आधार बताए जाएँगे जिसके विरुद्ध अपील बिना किसी तर्क या विवरण के प्रस्तुत की गई है और ऐसे आधारों को क्रमिक रूप से क्रमांकित किया जाएगा।

(3) उप-नियम (1) और (2) में दिए गए प्रावधान के सिवाय, दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का V) की प्रथम अनुसूची में आदेश XLI और आदेश XXI के प्रावधान यथावश्यक परिवर्तनों सहित धारा 173 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में प्रस्तुत अपीलों पर लागू होंगे।

15. उपरोक्त प्रावधान के मद्देनजर, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर सही रूप से पहुंचा है कि दावेदार प्रति-आपत्ति दायर करने के हकदार होंगे। हालाँकि, इसने दावेदारों के प्रति-आपत्ति दायर करने के अधिकार को केवल तभी प्रतिबंधित कर दिया है जब बीमा कंपनी द्वारा पटना उच्च न्यायालय के पिछले निर्णयों का हवाला देते हुए मुआवजे की राशि को चुनौती देने वाली अपील दायर की जाती है। यह माना गया है कि जब बीमा कंपनी ने मुआवजे की राशि को चुनौती नहीं दी है, बल्कि केवल इस आधार पर मुआवजा देने के अपने दायित्व को चुनौती दी है कि चालक और/या वाहन के मालिक द्वारा नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया गया है, तो दावेदारों के कहने पर प्रति-आपत्ति मान्य नहीं होगी।

16. इस न्यायालय की विद्वान तीन-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष ***दिल्ली नगर निगम एवं अन्य बनाम अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं खुफिया एजेंसी लिमिटेड***[1] के मामले में एक मुद्दा उठा कि क्या मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 39 के तहत अपील में,

1 (2004) 3 SCC 250

उतरदाता को प्रति-आपत्ति दायर करने का अधिकार है और यदि हाँ, तो क्या प्रति-आपत्ति पर सुनवाई की जानी चाहिए और गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए, हालाँकि जिस अपील के संदर्भ में प्रति-आपत्ति दायर की गई है, वह स्वयं ही अस्वीकार्य होने के कारण खारिज कर दी गई है।

17. इस न्यायालय ने उक्त निर्णय में इस प्रकार टिप्पणी की:

"**14.** अपील का अधिकार विधि की उत्पति है। अपील का कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं है। कोई भी अपील तब तक दायर, सुनवाई या गुण-दोष के आधार पर निर्धारित नहीं की जा सकती जब तक कि क़ानून अपीलकर्ता को अधिकार और न्यायालय को ऐसा करने की शक्ति प्रदान न करे। अधिनियम की धारा 39, जहाँ तक इस अधिनियम के तहत पारित आदेशों का संबंध है, केवल उन आदेशों के विरुद्ध अपील दायर करने का अधिकार प्रदान करती है जो धारा 39 की उप-धारा (1) के खंड (i) से (vi) में दिए गए किसी भी विवरण के अंतर्गत आते हों। संसद ने उप-धारा (1) के पाठ में "और किसी अन्य से नहीं" अभिव्यक्ति को सम्मिलित करके, अधिनियम के तहत पारित किसी भी आदेश के विरुद्ध, जो उपर्युक्त खंड (i) से (vi) के अंतर्गत नहीं आता है, दायर की जा रही किसी भी अन्य अपील को विशेष रूप से बाहर करने का ध्यान रखा है। धारा 41 का खंड (क) दीवानी प्रक्रिया संहिता में निहित सभी प्रावधानों की प्रयोज्यता का विस्तार करता है। 1908 के अनुच्छेद 15 के अनुसार, (i) अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय के समक्ष सभी कार्यवाहियाँ, और (ii) अधिनियम के अंतर्गत सभी अपीलें। हालाँकि, दीवानी प्रक्रिया संहिता के ऐसे प्रावधानों की प्रयोज्यता को बाहर रखा जाएगा जो अधिनियम और/या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के साथ असंगत हों। इन प्रावधानों को सरलता से पढ़ने पर पता चलता है कि धारा 39 के अंतर्गत दायर सभी अपीलों पर, दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधान लागू होंगे। इसमें अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत अपीलों

पर आदेश 41 की प्रयोज्यता, जिसमें नियम 22 के अंतर्गत कोई भी प्रति-आपत्ति लेने का अधिकार शामिल है, भी शामिल है।

15. प्रति-आपत्ति प्रस्तुत करने का अधिकार अपील प्रस्तुत करने के अधिकार का हिस्सा है। जब आक्षेपित डिक्री या आदेश आंशिक रूप से एक पक्ष के पक्ष में और आंशिक रूप से दूसरे पक्ष के पक्ष में हो, तो एक पक्ष मुकदमे को समाप्त करने के उद्देश्य से अपनी आंशिक सफलता से संतुष्ट हो सकता है। हालाँकि, वह अपने अपील के अधिकार का प्रयोग करना चाह सकता है यदि उसे पता चलता है कि दूसरा पक्ष विवाद को समाप्त करने में रुचि नहीं रखता है और अपीलीय मंच के समक्ष इसे आगे बढ़ाकर मामले को जारी रखने का प्रस्ताव रखता है। ऐसी परिस्थितियों में वह भी प्रति-आपत्ति प्रस्तुत करके अपील दायर करने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है। इस प्रकार, आक्षेपित डिक्री या आदेश पर कोई भी प्रति-आपत्ति प्रस्तुत करना अपील के अधिकार का प्रयोग है, हालाँकि ऐसा अधिकार प्रति-आपत्ति प्रस्तुत करने के रूप में प्रयोग किया जाता है। मूल अधिकार अपील का अधिकार है; प्रति-आपत्ति का रूप प्रक्रिया का विषय है।

16. यद्यपि उपर्युक्त विधि का कथन प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों को पढ़ने से सरलता से प्रवाहित होता है, फिर भी कुछ उपलब्ध निर्णयों पर भी ध्यान दिया जा सकता है। *बहादुरमल बनाम बिजातुन्निसा बेगम [एआईआर 1964 आंध्र प्रदेश 365: (1964) 1 एएन डब्ल्यूआर 290]* में न्यायमूर्ति जगनमोहन रेड्डी (तत्कालीन माननीय न्यायमूर्ति) की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने हैदराबाद जागीरदार ऋण निपटान अधिनियम, 1952 की धारा 47 से 49 के तहत दायर एक अपील में प्रति-आपत्ति को स्वीकार्य माना क्योंकि दीवानी प्रक्रिया संहिता के प्रावधान धारा 51 के आधार पर सामान्य रूप से लागू होते थे। उस अधिनियम के तहत अपीलों पर आदेश 41 नियम 22 की प्रयोज्यता को केवल इसलिए अपवर्जित नहीं माना गया क्योंकि अपील के आधार और न्यायालय शुल्क को

नियंत्रित करने वाले प्रावधान विशेष रूप से हैदराबाद अधिनियम में अधिनियमित किए गए थे। *इनायतुल्लाह खान बनाम दीवानचंद महाजन* [एआईआर 1959 मध्य प्रदेश 58 : 1958 मध्य प्रदेश एलजे 786] में मुख्य न्यायाधीश *एम. हिदायतुल्लाह* (तत्कालीन माननीय न्यायमूर्ति) ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 116-क के अंतर्गत एक चुनाव अपील में प्रति-आपत्ति की स्वीकार्यता को बरकरार रखा क्योंकि धारा 116ए- के अंतर्गत एक अपील की सुनवाई करने वाले अपीलीय न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय को उन्हीं शक्तियों, अधिकार क्षेत्र और प्राधिकार का प्रयोग करने और उसी प्रक्रिया का पालन करने का आदेश दिया गया था जैसा कि वह दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक दीवानी अपील के संबंध में प्रयोग या पालन करता। *रामाश्रय सिंह बनाम बिभीषण सिन्हा [एआईआर 1950 कोलकता 372]* में, मुख्य न्यायाधीश हैरिस और न्यायमूर्ति बछावत (तब उनके माननीय न्यायाधीश थे) की खंडपीठ ने यह माना कि बंगाल साहूकार अधिनियम, 1940 की धारा 38 द्वारा अपील का अधिकार प्रदान किया जाना, जिसमें आदेश की अपील उसी प्रकार की जा सकती है जैसे कि वह न्यायालय का आदेश हो, उतरदाता को प्रति-आपत्ति दायर करने का अधिकार देता है क्योंकि अपील की सुनवाई का अधिकार एक पूर्व-स्थापित दीवानी न्यायालय, अर्थात् जिला न्यायाधीश के न्यायालय को प्रदान किया गया था और ऐसी अपील को विनियमित करने की प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा गया था। *ए.एल.ए. अलगप्पा चेट्टियार बनाम चोकलिंगम चेट्टी [एआईआर 1919 मद्रास 784 : आईएलआर 41 मद्रास 904 (एफबी)*] में, मुख्य न्यायाधीश वालिस की अध्यक्षता में मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने यह माना कि प्रति-आपत्ति ज्ञापन के माध्यम से आगे बढ़ने का उतरदाता का अधिकार विरोधी पक्ष द्वारा अपील दायर करने से पूरी तरह संबद्ध था और इसलिए प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1907 की धारा 46 और 47 के तहत अपील में, प्रति-आपत्ति धारणीय थी क्योंकि दीवानी प्रक्रिया संहिता में निर्धारित प्रक्रिया मानक प्रक्रिया है और दिवालियेपन के मामलों में

शक्तियों का प्रयोग करने वाले न्यायालयों पर लागू होती है।

17. सुविधानुसार, हम इस न्यायालय द्वारा *बारू राम बनाम प्रसन्नी [एआईआर 1959 एससी 93: 1959 एससीआर 1403]* में की गई टिप्पणियों का भी उल्लेख कर सकते हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 116-क के अनुसार, उच्च न्यायालय द्वारा उस अधिनियम की धारा 98 या धारा 99 के अंतर्गत दिए गए प्रत्येक आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। धारा 116-ग के अनुसार, ऐसी प्रत्येक अपील की सुनवाई और निर्धारण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यथाशीघ्र किया जाएगा और उस पर निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा अपने मूल दीवानी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए पारित किसी भी अंतिम आदेश के विरुद्ध किसी अपील की सुनवाई और निर्धारण के लिए लागू प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा, जो उस अधिनियम और नियमों, यदि कोई हों, के प्रावधानों के अधीन होगा। दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 और न्यायालय के नियमों के सभी प्रावधान, जहाँ तक हो सके, ऐसी अपील के संबंध में लागू होंगे। पी.बी. न्यायमूर्ति गजेंद्रगढ़कर (जैसा कि उस समय माननीय न्यायमूर्ति थे) ने न्यायालय की ओर से बोलते हुए यह टिप्पणी की: (एआईआर पृष्ठ 99, कंडिका 11)

"इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक साधारण दीवानी अपील में, उतरदाता अपील के तहत डिक्री का समर्थन करने का हकदार होगा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसके पक्ष में दिए गए आधारों के अलावा अन्य आधारों पर। दीवानी प्रक्रिया संहिता का आदेश 41 नियम 22, जो उतरदाता को प्रति-आपत्ति दायर करने की अनुमति देता है, उतरदाता को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध तय किए गए किसी भी आधार पर डिक्री का समर्थन करने के अधिकार को मान्यता देता है। वर्तमान मामले में उतरदाता 1 द्वारा कोई अपील नहीं की जा सकती थी क्योंकि वह यह घोषणा प्राप्त करने में सफल रही थी कि अपीलकर्ता का चुनाव शून्य था और इसलिए उसे उच्च न्यायालय के अंतिम निष्कर्ष का

समर्थन करने का अधिकार होना चाहिए यह तर्क देकर कि उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया अन्य निष्कर्ष जो मामले की जड़ तक जाएगा, गलत है। प्रथम दृष्टया इस तर्क में कुछ बल प्रतीत होता है;"

हालाँकि, न्यायालय ने इस पर कोई अंतिम राय व्यक्त नहीं की क्योंकि उस अपील में इस बिंदु पर निर्णय लेना आवश्यक नहीं समझा गया।

18. इसलिए, हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि प्रति-आपत्ति लेने का अधिकार, किसी क़ानून द्वारा प्रदत्त अपील के मूल अधिकार का प्रयोग है। चुनौती के उपलब्ध आधार, आलोचना किए गए निर्णय, डिक्री या आदेश के विरुद्ध, चाहे वह अपील हो या प्रति-आपत्ति, समान रहते हैं। अंतर अधिकार के प्रयोग के रूप और तरीके में है; सीमा अवधि (प्रारंभिक बिंदु) भी भिन्न होती है।

19. *अधीक्षण अभियंता बनाम बी. सुब्बा रेड्डी* [(1999) 4 एससीसी 423] में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने (एससीसी पृष्ठ 434, कंडिका 24 देखें) यह टिप्पणी की:

"यदि अधिनियम की धारा 39 के तहत प्रति-आपत्ति का कोई अधिकार नहीं दिया गया है, तो इसे अधिनियम की धारा 41 में नहीं पढ़ा जा सकता। प्रति-आपत्ति दायर करना प्रक्रियात्मक प्रकृति का नहीं है। अधिनियम की धारा 41 केवल यह निर्धारित करती है कि संहिता अधिनियम की धारा 39 के तहत अपील पर लागू होगी। इसलिए, हमारा यह मत है कि उतरदाता द्वारा प्रति-आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं थी...।"

ऐसी टिप्पणी सही नहीं है और कुछ गलत आधारों पर आधारित है। सबसे पहले, प्रति-आपत्ति का स्वरूप प्रक्रियात्मक है और यह केवल अपील के अधिकार का प्रयोग करने का एक तरीका है जो कि मूल है, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं। दूसरे, यह

केवल दीवानी प्रक्रिया संहिता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया नहीं है जिसे मध्यस्थता अधिनियम की धारा 41(क) द्वारा अधिनियम के तहत कार्यवाहियों पर लागू किया गया है; दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 का संपूर्ण स्वरूप न्यायालय के समक्ष सभी कार्यवाहियों और मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के तहत सभी अपीलों पर लागू किया गया है। यह प्रावधान अपनी प्रयोज्यता में सामान्य और व्यापक है जिसे कम नहीं किया जा सकता; एकमात्र अपवाद यह है कि मध्यस्थता अधिनियम और/या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधान दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधानों के साथ असंगत हो सकते हैं, ऐसी स्थिति में बाद की प्रयोज्यता को अपवर्जित माना जाएगा, लेकिन केवल असंगतता की सीमा तक। हम यह जोड़ना चाहेंगे कि *बी. सुब्बा रेड्डी मामले [(1999) 4 एससीसी 423] में* निर्धारित कानून से हमारी असहमति के कारण, ऐसा प्रतीत होता है कि उस मामले में यह प्रस्ताव काफी व्यापक रूप से प्रस्तुत किया गया था। वास्तव में, *बी. सुब्बा रेड्डी मामले [(1999) 4 एससीसी 423]* में न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या उच्च दर पर ब्याज के पंचाट से राहत की मांग करने वाली प्रति-आपत्ति स्वीकार्य थी, यद्यपि ऐसा आदेश अधिनियम की धारा 39(1) के क्षेत्राधिकार में नहीं आता था।

20. एक बार जब हम यह मान लेते हैं कि प्रति-आपत्ति लेने से जो प्रयोग किया जा रहा है वह स्वयं अपील का अधिकार है, तो इसका अर्थ यह है कि प्रति-आपत्ति का विषय और उसमें मांगी गई राहत धारा 39(1) की आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, यदि आवेदक अधिनियम की धारा 39(1) के प्रावधानों के अनुरूप अपील दायर करके उसी राहत की मांग कर सकता था, तो प्रति-आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। यदि प्रति-आपत्ति का विषय ऐसे आदेश पर आक्षेप लगाना है जो अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (1) के खंड (i) से (vi) द्वारा परिकल्पित किसी भी श्रेणी के दायरे में नहीं आता है, तो प्रति-आपत्ति पोषणीय नहीं होगी।

18. इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने यह माना है कि प्रति-आपत्ति प्रस्तुत करने का अधिकार अपील प्रस्तुत करने के अधिकार का हिस्सा है। यह माना गया है कि जब आक्षेपित डिक्री या आदेश आंशिक रूप से एक पक्ष के पक्ष में और आंशिक रूप से दूसरे पक्ष के पक्ष में हो, तो एक पक्ष मुकदमे को समाप्त करने के उद्देश्य से अपनी आंशिक सफलता से संतुष्ट हो सकता है। हालाँकि, यह माना गया है कि यदि वह पाता है कि दूसरा पक्ष मुकदमे को समाप्त करने में रुचि नहीं रखता है और अपीलीय मंच के समक्ष इसे आगे बढ़ाकर सूची को जीवित रखने का प्रस्ताव रखता है, तो वह अपील के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है। यह माना गया है कि वह भी ऐसे मामलों और परिस्थितियों में प्रति आपत्ति लेकर अपील दायर करने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है। इसके बाद यह माना गया है कि आक्षेपित डिक्री या आदेश पर कोई भी प्रति-आपत्ति करना अपील के अधिकार का प्रयोग है, हालाँकि ऐसा अधिकार प्रति-आपत्ति लेने के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह माना गया है कि मूल अधिकार अपील का अधिकार है और प्रति-आपत्ति का रूप प्रक्रिया का विषय है।

19. उक्त निर्णय पर पहुँचते समय, इस न्यायालय ने ***बहादुरमल बनाम बिजातुन्निसा बेगम***[2] के मामले में दिए गए निर्णय पर अवलंबन किया, जिसमें हैदराबाद जागीरदार ऋण निपटान अधिनियम, 1952 की धारा 47 से 49 के तहत दायर एक अपील में प्रति-आपत्ति की स्वीकार्यता के संबंध में एक मुद्दे पर विचार किया गया था। इसने ***इनायतुल्लाह खान बनाम दीवानचंद महाजन*** [3]के मामले में दिए गए निर्णय पर भी अवलंबन किया, जिसमें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 116ए के तहत एक चुनाव अपील में प्रति-आपत्ति की स्वीकार्यता को बरकरार रखा गया था। इसने आगे

2 AIR 1964 AP 365

3 AIR 1959 MP 58

रामाश्रय सिंह बनाम बिभीषण सिन्हा [4] एवं अन्य के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय पर अवलंबन किया जिसमें बंगाल साहूकार अधिनियम, 1940 की धारा 38 के तहत विचाराधीन अपील में प्रति-आपत्ति दायर करने के उतरदाता के अधिकार को बरकरार रखा है ।

20. इसने बारू **राम बनाम प्रसन्नी**[5] के मामले में इस न्यायालय की कुछ टिप्पणियों पर भी अवलंबन किया। यह न्यायालय ***अधीक्षण अभियंता एवं अन्य बनाम बी. सुब्बा रेड्डी***[6] के मामले में इस न्यायालय की विद्वान दो-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा लिए गए विपरीत दृष्टिकोण से सहमत नहीं था। हालाँकि, ऐसा मानते हुए, इस न्यायालय ने माना कि चूँकि मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 39 के तहत अपील का अधिकार केवल उप-धारा (1) के खंड (i) से (vi) तक ही सीमित था, इसलिए प्रति-आपत्ति भी उक्त आवश्यकता के अनुरूप होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, यह माना गया कि प्रति-आपत्ति केवल तभी स्वीकार्य होगी जब उसका विषय-वस्तु मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 39 की उप-धारा (1) के खंड (i) से (vi) के अंतर्गत निर्धारित किसी भी श्रेणी में आता हो।

21. इस न्यायालय ने आगे पाया कि संपूर्ण आदेश XLI नियम 22 दं.प्र.सं. उप-नियम (4) के प्रावधानों सहित प्रति-आपत्ति पर लागू होगा। यह माना गया कि यदि मूल अपील, धारा 39 की उप-धारा (1) के खंड (i) से (vi) में से किसी के अंतर्गत न आने वाले किसी आदेश के विरुद्ध दायर की गई हो, तो अक्षम या पोषणीय नहीं पाई जाती है, तो प्रति-आपत्ति भी उस आधार पर विफल हो जाएगी और गुण-दोष के आधार पर उस पर निर्णय नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि न्यायालय का मत यह है कि प्रति-आपत्ति तभी स्वीकार्य होगी जब अपील वैध रूप से स्वीकार्य हो।

---

4 AIR 1950 Cal 372

5 AIR 1959 SC 93:1959 SCR 1403

6 (1999)4 SCC 423

22. मोटर वाहन की धारा 173 का अवलोकन अधिनियम से यह स्पष्ट होता है कि उक्त प्रावधान मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 39 के तहत प्रतिबंधित अपील दायर करने के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करता है। यह प्रावधान करता है कि कोई भी व्यक्ति, जो दावा न्यायाधिकरण के किसी निर्णय से व्यथित है, उप-धारा (2) के प्रावधानों के अधीन, उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। धारा 173 की उप-धारा (2) के तहत लगाया गया प्रतिबंध, दावा न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय के विरुद्ध अपील दायर न करने के संबंध में है, यदि अपील में आक्षेपित राशि दस हजार रुपये से कम है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यह सीमा-सीमा के प्रावधानों के अधीन है।

23. जैसा कि ऊपर चर्चा की जा चुकी है, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने स्वयं यह टिप्पणी की है कि बिहार मोटर वाहन नियम, 1992 के नियम 249 के मद्देनजर, प्रति-आपत्ति की वैधता के संबंध में कोई मुद्दा नहीं हो सकता है। बिहार मोटर वाहन नियम, 1992 के नियम 249 के उप-नियम (3) से यह स्पष्ट होता है कि उप-नियम (1) और (2) में दिए गए प्रावधान को छोड़कर, दं.प्र.सं. की पहली अनुसूची में आदेश XLI और आदेश XXI के प्रावधान मोटर वाहन अधिनियम की धारा 173 के तहत उच्च न्यायालय में दायर अपीलों पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

24. मोटर वाहन अधिनियम की धारा 173; बिहार मोटर वाहन नियम, 1992 के नियम 249; और दं.प्र.सं. के आदेश XLI नियम 22 के प्रावधानों के संयुक्त अध्ययन से पता चलता है कि किसी भी पक्ष के अपील के अधिकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यह स्पष्ट है कि पंचाट के किसी भी भाग से व्यथित कोई भी पक्ष अपील करने का हकदार होगा। यह भी स्पष्ट है कि कोई भी उतरदाता, भले ही उसने डिक्री के किसी भी भाग के विरुद्ध अपील न की हो, अपने पक्ष में दिए गए निष्कर्ष का समर्थन करने के अलावा, डिक्री पर कोई भी प्रति-आपत्ति करने का भी हकदार है जो वह अपील के माध्यम से कर सकता

था।

25. जब अपीलकर्ता किसी अपील में उन आधारों में से कोई भी आधार उठा सकता था जिनसे वह व्यथित है, तो हम यह समझ नहीं पा रहे हैं कि किसी उतरदाता को दूसरे पक्ष द्वारा दायर अपील में प्रति-आपत्ति दायर करने से कैसे वंचित किया जा सकता है जिसमें पंचाट के उस भाग को चुनौती दी गई हो जिससे वह व्यथित था। हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा उल्लिखित उक्त भेद, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 173; बिहार मोटर वाहन नियम, 1992 के नियम 249; और दं.प्र.सं. के आदेश XLI नियम 22 के प्रावधानों के संयुक्त वाचन के अनुरूप नहीं है।

26. वास्तव में, प्रतिवादियों (बीमा कंपनी) द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में प्रार्थना खंड से यह देखा जा सकता है कि संपूर्ण निर्णय को प्रतिवादियों - बीमा कंपनी द्वारा चुनौती दी गई थी। इतना ही नहीं, बल्कि अपीलकर्ताओं (दावेदारों) को उक्त अपील में उतरदाता पक्ष के रूप में भी शामिल किया गया था। ऐसी परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं (दावेदारों) की प्रति-आपत्ति पर गुण-दोष के आधार पर विचार करने से इनकार करके त्रुटि की है।

27. इसका एक और पहलू भी है। दं.प्र.सं. के आदेश XLI के नियम 22 के उप-नियम (4) में विशेष रूप से प्रावधान है कि यदि मूल अपील वापस ले ली जाती है या चूक के कारण खारिज कर दी जाती है, तब भी प्रति-आपत्ति पर सुनवाई की जाएगी और अन्य पक्षों को ऐसी सूचना देने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा जैसा न्यायालय उचित समझे। इसलिए, हमारा विचार है कि, भले ही बीमा कंपनी की अपील अनुपस्थिति खारिज कर दी गई हो और बीमा कंपनी ने प्रस्तुत किया हो कि वे अपील को पुनर्जीवित करने में रुचि नहीं रखते हैं, फिर भी उच्च न्यायालय को अपीलकर्ताओं की प्रति-आपत्ति पर गुण-दोष के आधार पर और कानून के अनुसार निर्णय लेना आवश्यक था।

28. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। 21.1.2016 का आक्षेपित निर्णय और आदेश, जिसमें यह माना गया था कि वर्तमान अपीलकर्ताओं की प्रति-आपत्ति विचारणीय नहीं थी, अभिखंडित और अपास्त किया जाता है। वर्तमान अपीलकर्ताओं द्वारा दायर प्रति-आपत्ति पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय हेतु मामला उच्च न्यायालय को वापस भेजा जाता है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

अपील स्वीकार की जाती है।

दिव्या पांडे

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।